'सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ'

जयपुर देहात (दक्षिण) के नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का बजट सौगातों के लिए आभार जताया

जयपुर, 5 मार्च। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के आभार प्रदर्शन के लिए जयपुर देहात (दक्षिण) से आए प्रतिनिधिमंडल की आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट किसानों को आगे रखते हुए बनाया गया है। युवाओं के लिए भी सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियां और डेढ़ लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध् कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक प्रकरणों से राज्य का युवा परेशान था। हमने आते ही इन प्रकरणों में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। हमारे सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे अपराध मुक्त राजस्थान की दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य में गैंगवार और अपराध भी कम हुआ है।

शर्मा ने कहा कि हमने प्रदेश में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही, राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर का विस्तार होने के साथ ही, इसके आसपास के इलाकों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 'एक ही लाल, भजनलाल भजनलाल' और 'दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसले' जैसे नारों से पूरा पाण्डाल गुंजायमान हो उठा तथा लोगों ने अभूतपूर्व बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया। उपस्थित आमजन ने मुख्यमंत्री को 100 मीटर लम्बा साफा पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान जयपुर देहात (दक्षिण) के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व मंत्री कन्हैया लाल, बूथ मण्डल एवं जिला पदाधिकारी सहित, बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जयपुर के विस्तार के साथ, आस-पास के इलाकों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिये बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं।

जयपुर देहात (दक्षिण) की ओर से आए प्रतिनिधिमण्डल ने बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर आमजन ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

'अगर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, भारत हम पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है, यह सिस्टम अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, कभी भी नहीं था।"

उन्होंने "अमेरिका फर्स्ट" की नीति पर जोर देते हुए कहा, "अन्य देश कई सालों से हम पर टैरिफ लगा रहे हैं, अब हमारी बारी है। हम भी उनके खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे।"

प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिनमें कैनडा, मैक्सिको, चीन, यूरोपियन यूनियन और भारत शामिल हैं, को नई टैरिफ नीति में निशाना बनाया जाएगा। यह टैरिफ अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में भारी बदलाव करने की ट्रम्प की नीति का प्रमुख अंग है।

ट्रम्प हमेशा से मानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं और इसीलिए वे रैसिप्रोकल टैरिफ पर जोर दे रहे है, अपने पहले कार्यकाल में, उनके प्रशासन ने ऐसे ही फैसले किए थे, पर, उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया था।

नया टैरिफ शुल्क देश के आधार पर लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ शुल्क दर को ही नहीं बल्कि अन्य व्यवधानों पर भी ध्यान में रखा जाएगा।

'ट्रम्प की विदेश नीति में स्थायित्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न लौट जाए और उसे अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई फिर न शुरु कर दे।

अमेरिकन कांग्रेस के अपने भाषण में ट्रम्प ने एक खतरनाक आतंकवादी को सौंपने के लिए पाकिस्तान का आभार जताया। यह आतंकी काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट में शामिल था। इस धमाके में अफगान नागरिकों सहित, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणा के बाद लौट रहे थे।

ट्रम्प ने अपने भाषण में यह भी बताया कि अमेरिका की खुफिया सेवा का एक सीनियर अफसर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. के मुखिया से मिला और आतंकी को अमेरिका के सुपुर्द करने के मुद्दे पर काम किया, वह इस सप्ताह के अंत तक अमेरिका लौटने वाला है। इसी भाषण में उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत को कोसा और अमेरिकन कारों पर ज्यादा टैरिफ के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत, अमेरिकन कारों पर शत-प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प, आदतन फैक्ट चैक नहीं करते हैं और डेटा व तथ्यों के बारे जरा भी परवाह नहीं करते हैं।

असल में वर्तमान में भारत आयातित लग्ज़री कारों पर 70 प्रतिशत टैक्स लेता है, चाहे वह किसी भी देश से क्यों न हों, मोटर बाइक पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प ने पूर्व में हार्ली डेविडसन मोटर बाइक और इन पर लगे टैरिफ का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत ने मोटर बाइक से आयात शुल्क घटाया था। ट्रम्प डेटा और तथ्यों की परवाह नहीं करते हैं और अपनी ही सोच पर चलते हैं।

इसका नतीजा यह है कि अमेरिका अब जो करेगा, वो पूर्णतया अनिश्चित है। अमेरिका के विश्वस्त मित्र, जो कई दशकों से अमेरिका के साथ थे, अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहे हैं। ताईवान दशकों से अमेरिकन सपोर्ट पर आश्रित था, पर अब अमेरिका का विकल्प ढूंढ रहा है। ताईवान, चीन से अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर था। डॉनल्ड ट्रम्प के एक्शन प्रतिशोधात्मक और विनाशकारी साबित हो रहे हैं। ट्रम्प ने ब्रिटेन को आदेश दिया है कि इंटैलीजैंस जानकारी किसी को न दी जाए, इस पर तुरंत अमल हो। अमेरिका ने यूक्रेन को भी गुप्तचर जानकारी देना रोक दिया है जो कि यूक्रेन की सैन्य कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका सहयोगी देशों को भी गुप्तचर जानकारी नहीं दे रहा है। इस भ्रम और तनाव के बीच एक देश है, जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और अमेरिका के पास इसका विकल्प नहीं है। अमेरिका के बढ़े हुए शुल्क का सामना कर रहे चीन की संसद ने शी जिनपिंग की अध्यक्षता में मौजूदा वर्ष के लिए अपनी आर्थिक योजना को अंतिम रूप दिया। ट्रम्प द्वारा लगाए गए शुल्क व तमाम धमकियों के बावजूद चीन ने 5 प्रतिशत ग्रोथ टारगैट निर्धारित किया है। इसके अलावा, अमेरिका के दण्डात्मक आर्थिक कदमों से निपटने के लिए चीन अन्य कदम उठा रहा है। चीन ने अमेरिकन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे उनके कामकाज तथा प्रॉफिट को नुकसान पहुँचा है। चीन ने अब अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों व कच्चे माल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था व कम्पनियों को नुकसान हो सकता है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण खनिजों का कुल 85 प्रतिशत चीन के आधिपत्य में है। ये पदार्थ रक्षा उद्योग व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका, यूक्रेन से यह पदार्थ हासिल करना चाहता है, पर ज़ैलैंस्की से विवाद के बाद यह योजना विफल हो गई है। ट्रम्प ने वादा किया है कि वे यह पदार्थ ग्रीनलैंड से हासिल करेंगे, चाहे जो हो जाए। संकीर्ण दृष्टिकोण वाले ट्रम्प अमेरिका के तटों से आगे नहीं देख पा रहे हैं। वे अपने ही बनाए गड्ढ़ों में गिर सकते हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यू.पी., ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थितियों को फ्रीज कर ही रखा है। स्टालिन ने एक जॉइन्ट एक्शन कमेटी बनाया जाना भी प्रस्तावित किया, जिसमें सभी दक्षिणी राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह समिति इस मामले में जनता में जागरुकता पैदा करे तथा सीटों की सम्भावित कमी को रोकने के लिये आवश्यक हो चुके संघर्ष को आगे बढ़ाये। इस संघर्ष के क्षेत्र और पहुँच को विस्तार देते हुये तथा इस प्रक्रिया में अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को शामिल करते हुये, स्टालिन ने इस मुद्दे को सबसे ऊपर पहुँचा दिया। यह मुद्दा राज्य विधानसभा के चुनावों तक की अवधि में छाया रहेगा तथा इसके साथ तीन भाषा फॉर्मूले का विवादास्पद मुद्दा भी जुड़ा रहेगा। इस प्रकार, उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा को बिल्कुल अलग-थलग कर देने की व्यवस्था कर दी है। विशेष रुप से, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये अन्नाद्रमुक तथा भाजपा के गठबंधन की बैक-चैनल चर्चाओं की पृष्ठभूमि में, परिसीमन तथा भाषा के भावनात्मक मुद्दे को लेकर हुई आज की मीटिंग ने उक्त दोनों पूर्व मित्र-दलों के बीच प्रभावी रुप से अलगाव पैदा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रसंगवश बता दें कि केवल भाजपा ने ही आज की इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, जिसमें कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुये तथा ये प्रस्ताव तमिल और तमिलनाडु के हित में माने गये। परिसीमन सम्बंधित प्रस्ताव में, इस कार्यवाही को नाजायज़ बताया गया। स्टालिन द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव को सर्वदलीय मीटिंग में सर्वसम्मिति से पारित कर दिया। प्रस्ताव में स्टालिन ने कहा, "चूँकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया, इसलिये इन राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या कम करना अनुचित है। केन्द्र को (सीटों के मामले में) 2026 के बाद के 30 वर्षों तक वर्तमान व्यवस्था यथावत रखनी चाहिये, क्योंकि वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी) ने वादा किया था कि परिसीमन का निर्णय 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। अन्य राज्यों से भी जनसंख्या - नियंत्रण के उपायों को क्रियान्वित कराया जाना आवश्यक है।" प्रस्ताव में भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की परिसीमन की कवायद की निन्दा भी की गई। सर्वदलीय मीटिंग के प्रस्ताव में इसे तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये गंभीर खतरा बताया। स्टालिन ने कहा कि "केन्द्र की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में राज्य के 39 सांसदों की आवाज़ को सुनने तक के लिये तैयार नहीं है। हमें 2026 की जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन का साफ तौर पर विरोध करना पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाना होगा।"

फिल्म स्टार विजय की अभी -अभी लॉन्च हुई राजनैतिक पार्टी "तमिलागा वैट्री कड़गम" तक भी इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल थी। इसके अलावा, भाजपा के मित्र दल, जैसे "पट्टाली मक्कल काची" तथा अन्य भी मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन भाजपा के दो अन्य मित्र दलों - "तमिल मनीला कांग्रेस" तथा अभिनेता सीमान के नेतृत्व वाली "नाम तमिल काची" ने मीटिंग का बहिष्कार किया। स्टालिन ने कहा, "परिसीमन दक्षिण भारत के ऊपर लटकी तलवार जैसा है। यह परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर होगा। अगर केन्द्र ने मौजूदा 543 लोकसभा क्षेत्र कायम रखे, तो तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में 8 सीटें कम कर दी जायेंगी।" स्टालिन ने समझाया कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 848 कर दी गई तथा परिसीमन प्रतिशत आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। स्टालिन ने कहा, "लेकिन, अगर परिसीमन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को सिर्फ 10 सीटें मिलेंगी। दोनों ही तरीकों से अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन तमिलनाडु की आवाज दबा दी जायेगी। हमें इस षडयंत्र को पराजित करना है।" मीटिंग में पारित एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है तो संविधान में ऐसा संशोधन किया जाये कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्यसभा में तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों की सीटें आनुपातिक रुप से बढ़ाई जायेंगी।

'राजीव गांधी शिक्षा की दृष्टि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस ने जहाँ अय्यर की टिप्पणियों को खारिज किया है और राजीव गांधी को भारत के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक बताया है, वहीं भाजपा ने अय्यर की टिप्पणियों का पूरा लाभ उठाया है। पार्टी के आई.टी. सैल के अमित मालवीय ने व्यापक रूप से उक्त वीडियो को शेयर किया है। वीडियो देखकर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह कहाँ शूट किया गया था।

अय्यर की टिप्पणियों ने भाजपा को विपक्ष के सवालों के विरूद्ध बोलने के लिए खूब मसाला दे दिया है, जो (विपक्ष) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्रियों को लेकर सवाल उठाता रहता है। अस्सी के दशक के मध्य में राजीव गांधी के निकट सलाहकारों में एक माने जाने वाले, अय्यर पार्टी नेतृत्व द्वारा अपनी निरंतर उपेक्षा के कारण काफी क्षुब्ध और नाराज़ हैं। पूर्व में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था, "द राजीव गाँधी आई न्यू-द फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन।"

कांग्रेस ने यह कहते हुए अय्यर की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है कि "पार्टी में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और उनके पास पार्टी का कोई महत्पूर्ण पद भी नहीं हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा, "उनके वक्तव्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।" पार्टी के वरिष्ठ नेता, तारिक अनवर ने कहा कि अच्छे से अच्छे लोग भी स्कूल और कॉलेज एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी राजनीति में फेल नहीं हुए। जब उन्हें जिम्मेवारी दी गई और वे प्रधानमंत्री बने, मेरा मानना है कि देश में बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ पाँच सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908